



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3386]	नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 11, 2017/अग्रहायण 20, 1939
No. 3386]	NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 11, 2017/AGRAHAYANA 20, 1939

गृह मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2017

का.आ.3860 (अ).— दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 432 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार, गृह मंत्रालय की दिनांक 9 नवम्बर, 1995 की अधिसूचना संख्या एसआरओ 3491, इस प्रकार के अधिकमण से पूर्व की गई या छोड़ दिए जाने वाली बातों के सिवाय, के अधिकमण में, निम्नांकित निदेश देती है, नामतः—

किसी कानून के तहत किसी ऐसे मामले से संबंधित अपराध हेतु जिसमें केन्द्र की कार्यकारी शक्ति लागू होती है, में कारावास दण्ड प्राप्त व्यक्ति द्वारा अथवा यदि वह व्यक्ति जेल में हैं, तो किसी और के द्वारा जब कारावास के दंड निष्पादन के निलंबन या कारावास के दंड के पूर्ण या आंशिक परिहार हेतु याचिका दायर की जाती है, तो ऐसे व्यक्ति के दंड निष्पादन को ऐसी अवधि, जो पंद्रह दिन से अधिक नहीं होगी, के लिए पैरा 2 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधधीन निलंबित कर दिया जाएगा और उसे पैरोल पर छोड़ दिया जाएगा। यदि राज्य सरकार, जिस की जेल में वह व्यक्ति बन्द है, इस बात पर संतुष्ट है कि ऐसे व्यक्ति को स्वयं को या उसके माता-पिता, पत्नी, पति या उसके बच्चे को किसी गंभीर बीमारी के कारण जान के खतरे की आशंका के कारण तत्काल पैरोल पर छोड़ना आवश्यक है।

2. पैराग्राफ 1 के तहत पैरोल पर छोड़ा गया व्यक्ति पैरोल अवधि के दौरान अवधि के दौरान विनिर्दिष्ट स्थान पर रहने का बांड भरेगा/वचन देगा और वह राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना, वहां से बाहर नहीं जाएगा व पैरोल की अवधि समाप्त होने पर जिस जेल में उसे रखा गया है, वहां वापस आ जाएगा और राज्य सरकार द्वारा आवश्यक समझी जाने वाली किन्हीं अन्य शर्तों का भी अनुपालन करेगा।

[फा. सं. V-17013/02/2016-पीआर]

टी.वी.एस.एन.प्रसाद, अपर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**ORDER**

New Delhi, the 6th December, 2017

S.O. 3860(E).—In exercise of the power conferred by Sub Section (5) of Section 432 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government, in supersession of the notification of Government of India in India in the Ministry of Home Affairs, number S.R.O. 3491, dated the 9th November, 1955, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, hereby gives the following directions, namely:-

Where a petition for suspension of the execution of a sentence of imprisonment or for remission of the whole or part of a sentence of imprisonment is made by or on behalf of a person sentenced to imprisonment of an offence under any law relating to matter to which the executive power of the Union extends and the person sentenced to an imprisonment is in jail, the execution of the sentence shall be suspended and such person released on parole, subject to the conditions specified in paragraph 2, for such period not exceeding fifteen days, if the Government of the State in which such person is detained in jail is satisfied that the immediate release of such person on parole is rendered necessary by reason of any illness constituting a grave threat to the life of such person or of a parent, wife, husband or child of such person.

2. A person released on parole under paragraph 1 shall enter into a bond, undertaking to reside during the period of the parole at a place specified therein and not depart therefrom, without the previous permission of the State Government and to return to the jail in which he is confined on expiry of the period of his parole, and to conform to such other conditions as the State Government may consider necessary.

[F. No. V-17013/02/2016-PR]

T.V.S.N. PRASAD, Addl. Secy.